

Published by:							
NEERAJ PUBLICATIONS							
Sales Office : 1507, 1st Floor, Nai Sarak, Delhi-110	006						
<i>E-mail</i> : info@neerajignoubooks.com <i>Website</i> : www.neerajignoubooks.com							
Reprint Edition with Updation of Sample Question Paper Only Typesetting by: Competent Computers Printed at: Novelty Printer							
<i>Notes:</i> 1. For the best & upto-date study & results, please prefer the recomm	ended textbooks / study material only						
 Polytic best & uppo-date study & results, piedse prejer die recommender Thisbock is just a GuideBock/ ReferenceBock published by NEER by a particular Board / University. 							
 The information and data etc. given in this Book are from the best of and upto-date information and data etc. see the Govt. of India Pu University. 							
 Publisher is not responsible for any omission or error though every care has been taken while preparing, printing, composing and proof reading of the Book. As all the Composing, Printing, Publishing and Proof Reading etc. are done by Human only and chances of Human Error could not be denied. If any reader is not satisfied, then he is requested not to buy this book. 							
 In case of any dispute whatsoever the maximum anybody ca for the price of the Book. 	ı claim against NEERAJ PUBLICA	TIONS is just					
 If anyone finds any mistake or error in this Book, he is requested to in and he would be provided the rectified Book free of cost. 	form the Publisher, so that the same co	uld be rectified					
7. The number of questions in NEERAJ study materials are indicative	e of general scope and design of the q	uestion paper.					
 Question Paper and their answers given in this Book provide you is prepared based on the memory only. However, the actual Qu distribution of marks and their level of difficulty. 	estion Paper might somewhat vary i	n its contents,					
9. Any type of ONLINE Sale/Resale of "NEERAJ BOOKS/NEERAJ IGNOU BOOKS" published by "NEERAJ PUBLICATIONS" on Websites, Web Portals, Online Shopping Sites, like Amazon, Flipkart, Ebay, Snapdeal, etc. is strictly not permitted without prior written permission from NEERAJ PUBLICATIONS. Any such online sale activity by an Individual, Company, Dealer, Bookseller, Book Trader or Distributor will be termed as ILLEGAL SALE of NEERAJ IGNOU BOOKS/NEERAJ BOOKS and will invite legal action against the offenders.							
10. Subject to Delhi Jurisdiction only.							
${ m }{ m C}$ Reserved with the Publishers only.							
Spl. Note: This book or part thereof cannot be translated or a criticism) without the written permission of the pu		or review or					
How to get Books by	Post (V.P.P.)	2					
If you want to Buy NEERAJ IGNOU BOOKS by Post (V.P.P.), then please order your complete requirement at our Website www.neerajignoubooks.com. You may also avail the 'Special Discount Offers' prevailing at that Particular Time							
(Time of Your Order). To have a look at the Details of the Course, Name of the Books, Printed Price & the Cover Pages (Titles) of our NEERAJ IGNOU BOOKS You may Visit/Surf our website www.neerajignoubooks.com . No Need To Pay In Advance, the Books Shall be Sent to you Through V.P.P. Post Parcel. All The Payment including the Price of the Books & the Postal Charges etc. are to be Paid to the Postman or to your Post Office at the time when You take the Delivery of the Books & they shall Pass the Value of the Goods to us by Charging some extra M.O. Charges. We usually dispatch the books nearly within 4-5 days after we receive your order and it takes Nearly 5 days in the postal service to reach your Destination (In total it take atleast 10 days).							
NEERAJ PUBI		S					
(Publishers of Educational Books)							
(An ISO 9001:2008 Certified Company) 1507, 1st Floor, NAI SARAK, DELHI - 110006							
Ph. 011-23260329, 45704411, 23244362, 23285501							
E-mail: info@neerajignoubooks.com Website: www.neerajignoubooks.com							

CONTENTS	
भारत में कृषि विकास	
(Agricultural Development in India)	
Question Bank – (Previous Year Solved Question Papers)
Question Paper—June, 2019 (Solved)	1-2
Question Paper—June, 2018 (Solved)	1-2
Question Paper—June, 2017 (Solved)	1-2
Question Paper—June, 2016 (Solved)	1
Question Paper—June, 2015 (Solved)	1-2
S.No. Chapterwise Reference Book	Page
कृषि और आर्थिक विकास (Agricultural and Economic Development))
1. कृषि और आर्थिक वृद्धि (Agriculture and Economic Growth)	1
2. भूमि उपयोग और फसल प्रतिरूप (Land Utilization and Cropping Patter	ns) 8
3. जल और सिंचाई संसाधन (Water and Irrigation Resources)	17
भारतीय कृषि : संस्थागत परिप्रेक्ष्य (Indian Agriculture: Institutional Perspec	tives)
- 4. स्वतन्त्रता पूर्व अवधि में भूमि और कृषि सम्बन्ध	26
(Land and Agrarian Relations During the Pre-Independence Period)	
5. स्वतन्त्रता के बाद की अवधि में भूमि और कृषि सम्बन्ध	32
(Land and Agrarian Relations During the Post-Independence Period)	
 पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन 	39
(Panchayati Raj and Local Self Government)	
योजनाओं के माध्यम से कृषि विकास (Agricultural Development Through the	e Plans)
7. भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका और महत्त्व (Role and Importance of Agriculture in Indian Economy)	47
8. भारतीय कृषि की विविध प्रवृत्तियाँ (Diversified Trends of Indian Agriculture)	53

<i>S.No</i> .	Chapter	Page
9.	भारत में वानिकी : कृषि सेक्टर से संबद्धता (Forestry in India: Linkage with Agriculture Sector)	58
10.	ग्रामीण औद्योगिकीकरण कार्यक्रम (Rural Industrialization Programme)	64
भारतीर	प्र कृषि में प्रौद्योगिकीय परिवर्तन (Technological Changes in Indian Agricul	ture)
11.	हरित क्रान्ति (Green Revolution)	73
12.	नई प्रौद्योगिकी और हितलाभों का वितरण (New Technology and Distribution of Gains)	80
13.	कृषि उत्पादकता में प्रवृत्तियाँ (Trends in Agricultural Productivity)	86
14.	नई और आविर्भावी कृषि कार्यप्रणालियाँ (New and Emerging Agricultural Practices)	94
	राज्य और कृषि सेक्टर (State and Agriculture Sector)	
15.	भारतीय कृषि में पूँजी निर्माण (Capital Formation in Indian Agriculture)	100
16.	भारत में कृषि विपणन (Agricultural Marketing in India)	108
17.	भारत में सहकारी आन्दोलन और कृषि (Cooperative Movement and Agriculture in India)	117
18.	संस्थागत वित्त, संविदा कृषि और खाद्य आपूर्ति शृंखला (Institutional Finance, Contract Farming and Food Supply Chain)	126
	कृषि क्षेत्र में समस्याएं-I (Issues of Agricultural Sector-I)	
19.	खाद्य सुरक्षा (Food Security)	133
20.	कृषि मूल्य नीति और खाद्य स्फीति (Agricultural Price Policy and Food Inflation)	143
21.	कृषि प्रगति का पर्यावरणीय प्रभाव (Environmental Impact of Agricultural Progress)	152
22.	नई कृषि रणनीति (Measures of Central Tendency)	162

S.No.	Chapter	Page
	कृषि क्षेत्र में समस्यायें-II (Issues in Agricultural Sector-II)	
23.	कृषि कराधान, साहाय्य और बीमा (Agricultural Taxation, Subsidies and Insurance)	171
24.	कृषि श्रमिक और मजदूरी (Agricultural Labour and Wages)	180
25.	छोटे किसानों की विपत्ति और मनरेगा (Small Farmer's Distress and MGNREGA)	192
	कृषिः अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ Agriculture and International Context	
26.	कृषि माल का विदेश व्यापार (Foreign Trade in Agricultural Goods)	201
27.	अंतर्राष्ट्रीय वचनबद्धताएँ (International Commitments)	213



QUESTION PAPER

(June – 2019)

(Solved)

भारत में कृषि विकास

समय : 3 घण्टे]

[अधिकतम अंक : 100

नोट: प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक खण्ड के निर्देशानुसार दीजिए।

खण्ड-क

प्रश्न 1. भारत में कृषि हेतु सिंचाई की आवश्यकता के पांच कारण बताइए। भारत में प्रकल्प के रूप में संचालित सिंचाई व्यवस्था के तीन मुख्य स्वरूप बताइए। भूतल के जल के प्रयोग को लेकर मुख्य चिन्ताएं क्या हैं?

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-3, पृष्ठ-20, 'भारत में सिंचाई', पृष्ठ-20, 'सिंचाई के प्रकार', पृष्ठ-20, 'भौमजल विषयक चिन्ताएं'

प्रश्न 2. क्या आप सहमत हैं कि 'संस्थागत विकास ही आर्थिक विकास है'? भारत में पंचायती राज संस्थाओं के उद्भव को स्पष्ट कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-6, पृष्ठ-40, 'संस्थागत', पृष्ठ-40, 'पंचायती राज संस्थाओं का विकास'

प्रश्न 3. कोई ऐसी दो कृषि पक्षीय विकास नीतियां समझाइए जिनके भूजल के अधारणीय प्रयोग रूपी प्रभाव भी हुए हैं। किन कारणों से कहा जाता है कि हरित क्रान्ति के फलस्वरूप आर्थिक विषमताएं और अधिक व्यापक हो गई हैं?

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-11, पृष्ठ-79, प्रश्न 8, पृष्ठ-74, 'हरित क्रान्ति का प्रभाव'

प्रश्न 4. कृषिक विपणन की वे विशेषताएं बताइए जो उसे अन्य बाजारों से भिन्न स्वरूप प्रदान करती हैं। छोटे किसानों की विपणन संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या युक्तियां सुझायी गई हैं?

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-16, पृष्ठ-109, 'भारत में कृषि विपणन व्यवस्था', पृष्ठ-114, प्रश्न 3

खण्ड–ख

किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर लिखें।

प्रश्न 5. भारत में भूमि सुधार कानूनों के चार मुख्य सार तत्त्व बताइए। भू-धारण सीमा कानूनों के निकृष्ट प्रदर्शन में किन कारकों का बडा योगदान रहा है;

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-5, पृष्ठ-33, 'भूमि सुधार व कृषि विकास', पृष्ठ-35, 'भुधारण सीमा'

प्रश्न 6. क्या आप सहमत है कि भारत की ग्रामीण औद्योगीकरण नीति का क्रियान्वयन उतना समाहनकारी नहीं रहा जितनी अपेक्षा थी? आपके मतानुसार आगामी वर्षों में इस त्रुटि को सुधारने के लिए क्या किया जाना चाहिए?

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-10, पृष्ठ-64, 'परिचय', पृष्ठ-66, 'भारत में ग्राम उद्योगों के संर्वधन के लिए नीतियां-एक विहंगावलोकन'

प्रश्न 7. क्या आप स्वीकार करेंगे कि छोटे किसानों को संस्थागत वित्त सुलभ कराने की प्रक्रिया ही उनके विरुद्ध रुझानों से भरी होती है?

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-25, पृष्ठ-192, 'राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम', पृष्ठ-193, 'NREGA की प्रस्थिति: पंचवर्षीय आकलन'

प्रश्न 8. स्तरानुसार खेती विधि किन क्षेत्रों में अपनाई जाती है? इस विधि से उत्पाद और पर्यावरणीय हानियां किस प्रकार न्यूनतम हो जाती हैं?

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-2, पृष्ठ-11, 'अन्तरासस्यन फसल', पृष्ठ-12, 'फसल प्रतिरूप में वर्तमान प्रवृत्तियों के दूरगामी प्रभाव'

प्रश्न 9. कृषि में सार्वजनिक निवेश मंद पड़ जाने के पांच महत्त्वपूर्ण कारणों की व्याख्या कीजिए। कृषि में निजी निवेश को प्रभावित करने वाले पांच कारक भी बताइए।

2 / NEERAJ : भारत में कृषि विकास (JUNE-2019)

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-15, पृष्ठ-103, 'सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा पूंजी निर्माण में ह्रास के कारण', पृष्ठ-104, 'कृषि में निजी पूंजी निर्माण के निर्धारक तत्त्व'

प्रश्न 10. विश्व व्यापार संगठन ने कृषिक व्यापार की किन विकृतियों को दूर करने की अभिकल्पना की थी? समझाइए कि विश्व व्यापार संगठन-कृषि पर समझौता मिलकर भारत जैसे विकासशील देशों के कृषि क्षेत्र को किस प्रकार पाशबद्ध कर लेते हैं?

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-27, पृष्ठ-213, 'परिचय', 'कृषि व्यापार में अर्न्तराष्ट्रीय चिन्ताओं के क्षेत्र', पृष्ठ-216, प्रश्न 1

खण्ड–ग

प्रश्न 11. किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(a) जानकारी की विसंगति किस प्रकार कृषि को प्रभावित करती है? एक उदाहरण द्वारा संक्षेप में समझाइए। उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-6, पृष्ठ-43, प्रश्न 3 (b) कुजनेट्स ने अर्थव्यवस्था में क्रषि के कौन-से

तीन योगदान सुझाए थे?

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-1, पृष्ठ-5, 'आर्थिक वृद्धि के लिए कृषि योगदान', अध्याय-7, पृष्ठ-51, प्रश्न 2

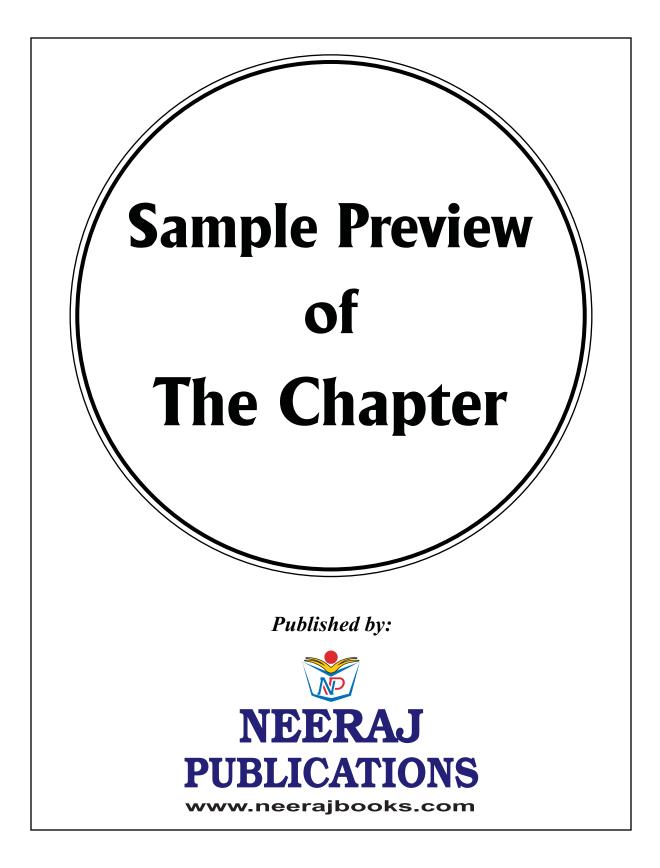
(c) किन तीन कारणों से भारत के छोटे किसान पर्याप्त मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं कर पाते?

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-14, पृष्ठ-95, 'रासायनिक खनिज उर्वरक', पृष्ठ-99, प्रश्न 3

(d) खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किन तीन क्षेत्र पर निरंतर कार्य करने की आवश्यकता है? समझाइए।

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-19, पृष्ठ-133, 'त्रुटियों पर लक्ष्य साधन'

Neeraj Publications www.neerajbooks.com





कृषि और आर्थिक विकास (Agriculture and Economic Development)

कृषि और आर्थिक वृद्धि (Agriculture and Economic Growth)

<u>परिचय</u>

भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत कृषि ही है। कृषि को देश की समग्र नीति का महत्त्वपूर्ण अंश माना जाता है। कृषि के द्वारा देश को जो आय प्राप्त होती है, वह शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों की वृद्धि के लिए सहायक मानी गई है। भारत की अर्थव्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने में भी कृषि का बहुत बड़ा योगदान है। परन्तु भारतीय अर्थव्यवस्था के कुल GDP में कृषि क्षेत्र के निर्धारित सापेक्ष महत्त्व में पिछले छह दशकों के दौरान काफी गिरावट देखने को मिली है, जो अर्थव्यवस्था के लिए उचित नहीं है। अत: अर्थव्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने के लिए उचित नहीं है। अत: अर्थव्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने के लिए कृषि का विकास अत्यधिक आवश्यक है। इसके लिए हमें कृषि विकास की आवश्यक शर्तों को जानना अति अनिवार्य हैं, जिसके विषय में इस अध्याय के अन्तर्गत पर्याप्त चर्चा की गई है।

अध्याय का विहंगावलोकन

कृषि विकास के लिए शर्तें : सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि

कृषि को आर्थिक विकास का महत्त्वपूर्ण भाग माना गया है। विभिन्न प्रकृतिवादियों के अनुसार कृषि कार्यों के द्वारा ही उत्पादन लागत से अधिक आर्थिक अधिशेषों को उत्पादित किया जा सकता है। इनके मतानुसार जितना आर्थिक अधिशेष कृषि द्वारा प्राप्त होता है, उतना अन्य कार्यों; जैसे विनिर्माण तथा वाणिज्य आदि से प्राप्त नहीं होता। अत: प्रकृतितन्त्रविदों ने कृषि को आर्थिक विकास का महत्त्वपूर्ण अंग माना है।

अठाहरवीं व उन्नीसवीं शताब्दी की शुरुआत में भी अनेक अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक विकास में कृषि की भूमिका को महत्त्वपूर्ण माना तथा कृषि की वृद्धि को उद्योगों की वृद्धि से जोड़ा। जैसे कि एडम स्मिथ ने आर्थिक विकास के लिए गैर-कृषि उत्पादनों की सहायता करने के लिये कृषि अधिशेष के उत्पादनों पर विचार किया। इन्होंने 'प्रौद्योगिकी निवेश तथा लाभ' के मध्य भी सम्बन्ध बताया। इनके अनुसार प्रौद्योगिकी का स्तर क्या होगा, यह निवेश पर निर्भर करेगा। निवेश के द्वारा लाभ का स्तर पता चलता है व लाभ आंशिक रूप से प्रौद्योगिकी के स्तर पर निर्भर करता है। इस प्रकार इन अर्थशास्त्रियों ने प्रत्यक्ष रूप से कृषि के विकास को उद्योग तथा प्रौद्योगिकी के साथ जोड़ा। लेकिन इनके मतानुसार आर्थिक वृद्धि अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर मानी गई। इसका कारण था कि आर्थिक संक्रमण काल की आरंभिक अवस्था में ज्यादातर अर्थव्यवस्थाएँ श्रमिक बल के भरण-पोषण के लिए कृषि पर ही निर्भर रहती हैं। 1945 के आस-पास ही विकास के अनेक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र बन गए, जिन्हें निम्नलिखित चार भागों में विभक्त किया गया–

- 1. लुईस का 'द्विक्षेत्रक (दो क्षेत्र) आर्थिक प्रतिमान' (1954)।
- फाई तथा रेनिस द्वारा प्रतिपादित 'औद्योगिकीकरण के लिए तीन प्रावस्था संबधन' (1961)।
- शूल्ल्ज-जॉर्गेनसन द्वारा रचित 'सेक्टर सम्बन्धी अन्तरण के लिये आवश्यक शर्ते' प्रतिमान (1964)।
- अनेक योगदानकर्त्ताओं द्वारा प्रस्तुत विकास युक्ति के रूप में कृषि पहलें या 'सन्तुलित वृद्धि दृष्टिकोण'।

द्विक्षेत्रक अर्थव्यवस्था प्रतिमान : लुईस का तर्क

डब्ल्यू. ऑर्थर लुईस का प्रतिमान मुख्यतः इस तथ्य पर निर्भर करता है कि विकासशील देशों में कृषि कार्यों के द्वारा जीवन– निर्वाह करने वाला एक विशाल श्रम बल विद्यमान रहता है। इसकी सीमान्त उत्पादकता बहुत कम होती थी, अत: निर्वाह मजदूरी स्तर पर उपलब्ध अधिवेशन श्रम बल को ज्यादा उत्पादनकारी क्षेत्र पर स्थानान्तरित किया जाता है। यह स्थानान्तरण कृषि क्षेत्र के निर्वाह से व मजदूरी से सम्बन्ध रखता है। इससे कृषि कार्यों के पूँजीवादी क्षेत्र में जाने के अवरोध को समाप्त किया जाता है। यह माना जाता है कि पूँजीवादी क्षेत्र में कार्यों को करने के लिये 'कुशल

2/NEERAJ : भारत में कृषि विकास

कामगारों' की आवश्यकता होती है, परन्तु लुईस ने इस बात में अधिक सच्चाई का अनुभव नहीं किया, क्योंकि लुईस के अनुसार कुशल कामगार भी प्रशिक्षित होते हैं, अत: अकुशल कामगारों को उचित प्रशिक्षण देकर कुशल बनाया जा सकता है।

ज्यादा निवेश तथा प्रौद्योगिकी की वजह से 'पूँजीवादी क्षेत्र' में श्रम की सीमान्त उत्पादकता कृषि क्षेत्र में प्रभावी मजदूरी दर की तुलना के उच्च कोटि की होगी। इससे पूँजी अधिशेष का निर्धारण होगा व इस पूँजी को पूँजी निर्माण के उच्चतर स्तरों में निवेश के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। जब यह निवेश बढ़ेगा, तो इसके दो लाभ होंगे-

पहला, पूँजीवादी क्षेत्र में श्रम की सीमान्त उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है।

दूसरा, रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराये जा सकते हैं।

यहाँ पर पूँजीवादी नियोक्ता कृषि से अतिरिक्त श्रमिकों की भर्ती उस समय करते हैं, जबकि श्रम की आपूर्ति मजदूरी प्रति लोचशीलता लिये होती है। लुईस का यह प्रतिमान मुख्यत: विवेकशील तथा पूर्ण प्रतिस्पर्धा की मान्यताओं आधारित है तथा इसे विशाल कृषि अर्थव्यवस्थाओं पर लागू किया जाता है। अन्य अर्थशास्त्रियों द्वारा प्रस्तुत की गई क्रमिक प्राप्ति लुईस के इस द्विक्षेत्रक सिद्धान्त को परिष्कृत करके इसे पूँजीवादी बाजार पर आधारित अर्थव्यवस्था की व्यवहारिकता के अनुकूल बनाती है।

लुईस का यह प्रतिमान आर्थिक विकास की प्रक्रिया को समझने में अपनी एक पूर्ण रूपरेखा प्रदान करता है। क्योंकि लुईस का मानना यह था कि श्रम स्थानान्तरण की प्रक्रिया अनिश्चित काल तक रखना सम्भव नहीं है, वरन किसी न किसी समय पर यह समाप्त होती ही है। अत: इन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया को अन्य श्रम अधिशेष वाले देशों से अप्रवासन प्रोत्साहित करके या निर्वाह मजदूरी दर पर श्रमिकों की पर्याप्त आपूर्ति वाले देशों को पूँजी निर्माण व निर्यात की प्रक्रिया द्वारा लागू करके जारी रखा जा सकता है। परन्तु लुईस के प्रतिमान के कई आलोचनात्मक पक्ष भी हैं, जो कि निम्नलिखित हैं–

- श्रम स्थानान्तरण की प्रक्रिया से लाभ व पूँजी निर्माण की दर को बनाया जा सकता है, परन्तु इससे कृषि मजदूरी अपेक्षा से अधिक निम्न दशा तक आ सकती है।
- पूँजीवादी नियोक्ताओं के द्वारा यहाँ अधिशेष का प्रयोग गैर-उत्पादनकारी कार्यों में किया जा सकता है।
- ग्रामीण गरीबों के द्वारा स्वयं की प्रत्याशाओं को पूर्ण करने के लिए खपत पर अधिक व बचत पर कम ध्यान दिया जाता है, जिससे विकास कार्य धीमा हो सकता है।

अतः इन आलोचनाओं को ध्यान में रखते हुए रेनिस व फाई ने एक मॉडल प्रस्तुत किया, जो लुईस के मॉडल का सुधारात्मक रूप था। इन्होंने कृषि क्षेत्र के 'उपेक्षित' स्तर का विश्लेषण किया तथा कृषि उत्पादकता में वृद्धि की संभावना का प्रयोग करके स्थैतिक (static) विश्लेषण को सामान्य नियम के रूप में प्रस्तुत किया।

औद्यागिकीकरण से त्रि-प्रावस्था सम्बन्धन : फाई और रेनिस

फाई तथा रेनिस के द्वारा औद्योगिकीकरण व कृषि के अधिशेष श्रमिक स्थानान्तरण से सम्बन्धित तीन अवस्थाएँ बताई गईं–

पहली अवस्था – इस अवस्था के अन्तर्गत 'अधिशेष श्रमिकों' का संग्रह किया जाता है। इस प्रावस्था में कृषि उद्योग से श्रमिकों के स्थानान्तरण से कृषि उत्पादन कार्यों पर किसी भी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता।

दूसरी अवस्था-इस अवस्था के अन्तर्गत अधिशेष श्रमिक संग्रह वाला होता है। यह अवस्था लुईस के वर्तन बिन्दु (संधिकाय) की अवस्था होती है। इसमें कृषि से उद्योग में श्रम स्थानान्तरण के लिए सकारात्मक अवसरों की प्राप्ति होगी। फलस्वरूप कृषि उत्पादों में सीमान्त गिरावट होने के साथ-साथ अर्थव्यवस्था के उत्पादों में वृद्धि होगी।

तीसरी अवस्था-तीसरी अवस्था के अन्तर्गत कृषि श्रम का सीमान्त उत्पाद औद्योगिक मजदूरी के समान हो जाता है। अर्थात मजदूरी के अनुसार ही उत्पादन होगा। परन्तु इस अवस्था में आर्थिक संवृद्धि की प्रगति निम्नलिखित प्रकार से संशोधित हो सकती है-

- (i) प्रौद्योगिकीय रूप से प्रगति करके उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है।
- (ii) उन्नतशील आधारभूत संरचना के द्वारा अर्थव्यवस्था की समावेश क्षमता को बढा़या जा सकता है।

यहाँ पर इस प्रतिमान का मुख्य निष्कर्ष यह आता है कि आर्थिक रूपान्तरण की शुरुआती अवस्थाओं के दौरान कृषि समग्र आर्थिक वृद्धि को कोई भी हानि पहुँचाये बिना अधिशेष श्रम को प्रस्तुत करता है। परन्तु यह जरूरी नहीं है कि बाद की अवस्थाओं में भी यह दशा उत्पन्न हो। इस विषय में शूल्त्ज व जॉर्गेनसन ने अपना प्रतिमान प्रस्तुत किया, जिसमें आवश्यक बातों के विषय में चर्चा की गई।

सेक्टर सम्बन्धी अन्तरण के लिये आवश्यक शर्तें : शूल्ज- जॉर्गेनसन

शूल्त्ज ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि कृषि में श्रम की सीमान्त उत्पादकता का ह्वास होता है। साथ ही इन्होंने यह भी कहा कि ह्वास तो होता है, परन्तु उत्पादकता कभी भी शून्य अथवा नकारात्मक नहीं होती। इनके अनुसार निम्नलिखित दो महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर बल दिया गया–

- वे कौन सी दशाएँ हैं, जिनमें कृषि से अतिरिक्त श्रम को कृषि में उत्पादन घटाए बिना स्थानान्तरित किया जा सकता है?
- संभाव्य श्रम बल की क्या अपेक्षाएँ हैं, जिससे यह पारस्परिक रूप से संपूरक रूप में दोनों क्षेत्रों को लाभान्वित कर सके?

यहाँ पर शूल्ल्ज ने 'मानव पूंजी' का विचार प्रस्तुत किया है। इन्होंने बताया कि एक कुशल श्रमिक बनने के लिये शिक्षा अनिवार्य तत्त्व है। शिक्षा के द्वारा ही अनुभवहीन तथा अकुशल

कृषि और आर्थिक वृद्धि/3

श्रमिक को कुशलता प्रदान की जा सकती है। साथ ही किसान शिक्षित होकर किसी भी प्रकार के शोषण से बच सकते हैं। शूल्त्ज के समकालीन जॉर्गेनसन ने इस मुद्दे को संसाधनों के अन्त: क्षेत्र प्रवाह के दूष्टिकोण से देखते हुए कहा कि गैर कृषि से क्षेत्र की वृद्धि धनात्मकता की तरफ तथा बढ़ते हुए कृषि अधिशेषों पर निर्भर रहती है। जार्गेन्सन ने मुख्य रूप से यह माना कि कृषि में तकनीकी परिवर्तन तीव्रता से नहीं होते। इसके दो कारण हैं–

पहला, कृषि कभी भी खाद्य अधिशेष उत्पन्न नहीं करती है। दूसरा, कृषि कभी उद्योगों के लिये अपने अधिशेष श्रमिक छोड़ सकती है।

इसलिये शूल्त्ज व जॉर्गेन्सन के द्वारा यह बताया गया कि कृषि तथा उद्योगों की एक साथ होने वाली वृद्धि ही टिकाऊ वृद्धि तथा 'अधिशेष श्रम' की सफलता के लिए अनिवार्य है।

पहले कृषि बनाम सन्तुलित वृद्धि दृष्टिकोण

आर्थिक रूपान्तरण की शुरुआती अवस्थाओं में जनसंख्या का एक बड़ा भाग गाँवों में रहता है, जो पूर्णतः कृषि पर ही निर्भर है। परन्तु इनके लिये कृषि कार्यों द्वारा अपनी आय को बढाया नहीं जा सकता। ये कृषक गरीब व कम पढ़े-लिखे होते हैं, जिससे ये औद्योगिक क्षेत्र में भी कार्य नहीं कर सकते। अतः इनके लिये रोजेनस्टीन रोड द्वारा 'बिग पुश' अथवा 'प्रबल चेष्टा' का सिद्धान्त प्रस्तुत किया गया। इस सिद्धान्त का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के अलग-अलग क्षेत्रों को उत्पादन सुविधायें प्रदान करना था।

बिग पुश ने न्यूनतम उच्च मात्राओं को बढ़ाया तथा कृषि व गैर-कृषि दोनों ही क्षेत्र में संतुलित संवृद्धि को सरल बनाया। इसके अन्तर्गत कृषि व गैर-कृषि दोनों ही क्षेत्रों में किया जाने वाला निवेश लाभ प्रदान करेगा। इसके निम्नलिखित लाभ हो सकते हैं-

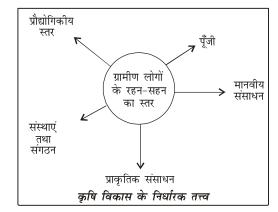
- ग्रामीण आय में वृद्धि होगी तथा औद्योगिक व गैर-कृषि माल में भी वृद्धि होगी।
- विशाल जनसंख्या की रुचिनुसार माल का स्तर बढा़या जायेगा।
- विदेशी व्यापार से औद्योगिक पूँजी में प्रवेश करने के लिए कृषि की क्षमता में सुधार लाना।

अत: इन सभी तर्कों के द्वारा कृषि-कार्यों को विकसित किया जा सकता है। साथ ही ये सभी तर्क कृषि विकास को प्राथमिकता प्रदान करते हैं।

कृषि विकास के निर्धारक तत्त्व

कृषि विकास अनेक प्रकार के कारकों से प्रभावित होता है। ये कारक भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, संस्थागत, राजनीतिक तथा प्रौद्योगिकीय आदि होते हैं। इन सभी कारकों द्वारा भिन्न-भिन्न स्तरों पर कार्य किया जाता है; जैसे कि पारिवारिक स्तर, जिला स्तर, ग्रामीण स्तर आदि तथा इन्हें नियन्त्रण करने की विधि के द्वारा ही इनके विकास के अनुकूल व प्रतिकूल प्रभावों को भी देखा जाता है।

यहाँ पर विशेषत: 'ग्रामीण आधारभूत संरचना' को कृषि उत्पादन व उत्पादकता वृद्धि का मुख्य तत्त्व माना गया है। इसके अन्तर्गत अनेक कारक जैसे कि सड़कें, बिजली आपूर्ति तथा सिंचाई, बैंकिंग आदि को भी महत्त्व दिया जाता है तथा कृषि से सम्बन्धित विशेष स्वरूप को 'सामाजिक आधारभूत संरचना' का नाम दिया जाता है। इस संरचना के अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएँ, सूचना-प्रसारण प्रणालियाँ तथा कृषि अनुसंधान से सम्बन्धित कारक आते हैं। अत: यहाँ कृषि विकास के निम्नलिखित निर्धारक तत्त्वों को प्रमुख माना गया है-



यहाँ पर कृषि में सार्वजनिक निवेश विकासशील अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत शीत भंडारण, विपणन तथा बिक्री केन्द्रों आदि को महत्त्वपूर्ण माना जाता है। यहां पर एक तथ्य यह भी हैं कि सकल पूँजी निर्माण के अनुपात के रूप में सार्वजनिक निवेश के अनुपात में पूर्णत: गिरावट आई है। यहाँ पर पूँजी निरुद्ध देशों में निवेश को आकर्षित करने के लिए मुख्यत: सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) को एक आधारभूत संरचना सुधार का विकल्प माना गया है। यह कृषि के लिए अति आवश्यक है।

कृषि विकास नीतियाँ

नीति का तात्पर्य किसी परिभाषित कार्य-योजना के निरूपण प्रख्यापन तथा अनुप्रयोग से लगाया जाता है। यहाँ पर कृषि कार्यों के विकास से सम्बन्धित नीतियों के विषय में चर्चा की जा रही है, जिसका अर्थ कृषि संवर्धन के निश्चित उद्देश्यों के बारे में सरकार द्वारा किये जाने वाले अनुकरण से लगाया जाता है। इसके अन्तर्गत नीति, कार्यक्रम तथा परियोजना के मध्य अन्तर बताना अति अनिवार्य होता है। अत: सर्वप्रथम हम इनके मध्य अन्तर को जानेंगे–

नीति–नीति एक अत्यन्त ही व्यापक शब्द है, जिसमें अनेक कार्यक्रमों को सम्मिलित किया जाता है।

कार्यक्रम–कार्यक्रम प्राय: कई परियोजनाओं को आपस में मिलाकर बनाये जाते हैं।

परियोजना–परियोजनाओं के अन्तर्गत उद्देश्यों, अवधि, कोष तथा निष्पादनकारी नीतियों को रखा जाता है।

एक कार्यक्रम के अन्तर्गत कई परियोजनाएं रखी जाती हैं। अत: कृषि विकास परियोजनाओं को ऐसे निवेश कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो संसाधनों के पूर्व-निर्धारित लक्ष्य प्राप्ति के लिए एक समय अवधि तक रखी जाती हैं।

www.neerajbooks.com

4/NEERAJ : भारत में कृषि विकास

कृषि विकास नीति के लक्ष्य

- कृषि विकास नीति के अनेक लक्ष्य होते हैं-
- (i) ये नीतियाँ प्राय: उन दशाओं के सुधार के लिए तैयार की जाती हैं, जिनमें गाँव के लोगों द्वारा कार्य किये जाते हैं।
- (ii) यहाँ पर नीतियों के लक्ष्य लोगों की इच्छाओं के द्वारा ही नियन्त्रित होते हैं।
- (iii) कृषि विकास नीति का सिद्धान्त सार्वजनिक नीति का सिद्धान्त होता है। यहाँ पर यदि लोग जिस तरीके से कार्य हो रहा है, उसे पसन्द नहीं करते, तो वे सार्वजनिक कार्यवाही के लिए दबाव पैदा करते हैं।
- (iv) यहाँ आदर्श स्थिति के लिए मानदंडों तथा छवियों को बनाया जाता है। यह मानदंड नीति लक्ष्य होते हैं तथा यहाँ कार्यक्रमों के उद्देश्य भी तैयार किये जाते हैं।

भारतीय संविधान के अन्तर्गत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों में आर्थिक नीति के दो प्रबल लक्ष्यों को निर्धारित किया जाता है, जो निम्नलिखित हैं-

- (i) राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना।
- (ii) राष्ट्रीय आय का वितरण समाज के सदस्यों के अनुसार उचित प्रकार से करके सुधार करना।

ये लक्ष्य पंचवर्षीय योजनाओं में भी सम्मिलित किये जाते हैं। वे लक्ष्य जो 'समावेशी वृद्धि' की प्राप्ति के लिए आवश्यक होते हैं, इन्हें निम्नलिखित चार भागों में विभक्त किया जाता है-

- (i) नागरिक जीवन-स्तर में सुधार लाना,
- (ii) 'उत्पादनकारी रोजगार' के अवसर उत्पन्न करना,
- (iii) सन्तुलित क्षेत्रीय विकास स्थापित करना तथा
- (iv) आत्म-निर्भरता प्राप्त करना।

ज्यादातर कृषि विकास नीतियों के अलग-अलग लक्ष्यों को मिलाकर एक मुख्य लक्ष्य का निर्माण किया जाता है। इन परियोजनाओं में सरकारी एजेन्सी विशेष के द्वारा कार्यों का क्रियान्वयन किया जाता है। ये एजेन्सियाँ निगरानी तथा नियन्त्रण के अधीन निजी तथा स्वयंसेवी एजेंसियों के क्रियान्वयन के लिए विशेष परियोजनाओं का निर्माण करती हैं। साथ ही विभिन्न शर्तों का निर्धारण किया जाता है। ये शर्तें मिलाकर परियोजनाओं व कार्यक्रमों का उचित क्रियान्वयन किया जाता है।

कृषि विकास नीतियों का वर्गीकरण

कृषि विकास नीतियों को दो प्रमुख भागों में विभक्त किया जाता है-(i) गुणात्मक नीति तथा (ii) परिमाणात्मक नीति।

- (i) गुणात्मक नीति–यह नीति नये संस्थानों के निर्माण, संशोधन तथा प्राइवेट फर्मों के संवर्धन द्वारा आर्थिक संरचना को बदलने का प्रयास करती है। यह नीति गुणों से सम्बन्धित होती है।
- (ii) परिमाणात्मक नीति–इस नीति के प्रभाव द्वारा कुछ प्रमुख आकारों में बदलाव लाये जा सकते हैं।

परन्तु यहाँ गुणात्मक व परिमाणात्मक दोनों ही प्रभावों को जाँचने के लिये एक उदाहरण शिक्षा प्रणाली के विषय में बताया जा सकता है, जैसे–नि:शुल्क शिक्षा प्रणाली की शुरुआत करना। इससे गुणात्मक तथा परिमाणात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तनों को देखा जा सकता है; जैसे कि गुणात्मक अर्थात आर्थिक संरचना परिवर्तन व परिमाणात्मक अर्थात सेवा के लिए लिया गया शुल्क। हेडी ने इस नीति को दो वर्गों में वर्गीकृत किया है–

- (i) विकास नीतियाँ-इसमें संसाधनों आदि की पूर्ति के लिए प्रयास किये गये।
- (ii) प्रतिपूर्ति नीतियाँ-इसमें लक्ष्य समूहों की प्रतिपूर्ति की जाती है।

कृषि विकास : औद्योगिकीकरण की प्रस्तावना

लुईस के सिद्धान्त के अनुसार, आर्थिक रूपान्तरण की प्रक्रिया प्रत्येक अर्थव्यवस्था पर समान रूप से लागू होती है। लेकिन देश के रूपान्तरण की गति यहाँ उस गति से अलग होती है, जिस गति पर देश की आवश्यक क्रियाविधियाँ स्थापित होती हैं। इस रूपान्तरण के अन्तर्गत कृषि आश्रित श्रमिक बल का हास होगा व गैर-कृषि क्षेत्र के उद्योग तथा सेवाओं में वृद्धि होगी। निम्नप्रदत्त तालिका के द्वारा भारत व विकसित अर्थव्यवस्थाओं में रोजगार तथा आय के तीन मुख्य क्षेत्रों के सापेक्ष अंशों के विषय में जानकारी प्रदान की जा रही है-

भारत और विकसित अर्थव्यवस्थाओं में रोजगार और आय में संरचनात्मक संयोजन

			-	प्रतिशत
प्रमुख	विकसित अर्थव्यवस्था		भारत (2009-10)	
आर्थिक	2000 के बाद			
क्षेत्र	आय	रोजगार	आय	रोजगार
कृषि	1-4	1-5	14.6	52
उद्योग	22-30	21-33	28.6	14
सेवाएं	68-73	63-74	57.2	34

तालिका के अनुसार निम्नलिखित बिन्दुओं को देखा जा सकता है–

- (i) कृषि क्षेत्र के अन्तर्गत कामगारों का अनुपात 52% है तथा
 यह सीमा विकसित देशों में 1 से 5% तक है।
- (ii) भारत के औद्योगिक रोजगार को 14% तक देखा गया है, जो विकसित अर्थव्यवस्थाओं के अंश का आधा हिस्सा है तथा 1950 से 2010 के मध्य यह औद्योगिक स्तर 4 से 5% तक वृद्धि प्राप्त कर चुका है।

(iii) भारत के औद्योगिकीकरण में कमी आई है, परन्तु कृषि रोजगार के अंश में यहाँ कोई गिरावट नहीं आई है। यह स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय 72% था, जो थोड़ा-सा घट कर 52% तक हुआ है।

अत: लुईस द्वारा समझाया गया है कि विकसित अर्थव्यवस्था के स्तर की प्राप्ति में भारत को अभी भी अनेक प्रयास करने हैं।

www.neerajbooks.com